

किशोरों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति गंभीर चुनौती

लेखक- ललित गर्ग

बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर नगोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा? बहुताल, इस हृदयविदारक एवं त्रासद घटना ने नयी बन रही समाज एवं परिवार व्यवस्था पर अनेक सवाल खड़े किये हैं। सवाल नये बन रहे समाज की नैतिकता एवं चित्रि से भी जुड़े हैं। निश्चित ही किसी परिवार की उम्मीदों का यूकल्प होना मर्मांतक एवं खौफनाक ही है। लेकिन सवाल ये है कि चौटह-पंद्रह साल के किसी भी पर यूकिन्ही लड़कियों को छेड़ने के आरोप क्यों लग रहे हैं?

भारतीय बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति एवं क्रूर मानसिकता विनाजनक है, नये भारत एवं विकसित भारत के भाल पर यह बदनुमा दाग है। पिछले कुछ समय से स्कूली बच्चों में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति निश्चित रूप से डरावनी, मर्मातिक एवं खीफनाक है। विंता का बड़ा कारण इसलिए भी है यद्योऽपि जिस उम्र में बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है, उसी उम्र में कई बच्चों में आक्रामकता एवं क्रूर मानसिकता घर करने लगी है और उनका व्यवहार हिंसक होता जा रहा है। फैथल जनपद के गांव धनीरी में दो किशोरों की निर्मम एवं क्रूर हत्या की हृदयविदारक घटना न केवल उद्देलित एवं भयभीत करने वाली है बल्कि विनाजनक है। चौदह-पंद्रह साल के दो किशोरों की गल रेतकर हत्या कर देना और वह भी उनके हमउम्र साथियों द्वारा, हर संवेदनशील इंसान को हिला देने वाली डरावनी एवं खीफनाक घटना है, जो किशोरों में पनप रहे हिंसक बर्ताव एवं हिंसक मानसिकता का विनाना एवं धातक रूप है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई-लिखाई और खेलकूद में व्यस्त रहना चाहिए, उसमें उनमें बढ़ती आक्रामकता, हिंसा एवं क्रूरता एक अस्वाभाविक और परेशान करने वाली बात है। जाहिर है दसवीं-ग्राहवीं के छात्रों की क्रूर हत्या हमारे समाज में बढ़ती संवेदनहीनता को भी दर्शाती है। ऐसी कई अन्य घटनाओं में स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने अपने सहपाठी पर चाकू या किसी धातक हथियार से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। अमेरिका की तर्ज पर भारत के बच्चों में हिंसक मानसिकता का पनपना हमारी शिक्षा, परिवारिक एवं सामाजिक संरचना पर कई सवाल खड़े करती हैं। जैसाकि घटना से सबधित तथ्यों में बताया गया कि हत्या में शामिल युवक धनीरी गांव के ही थे और कुछ दिन पहले किशोरों पर हल्पा आरोप लाया था। किसी उनकी बहनों से छेड़खानी करते थे। निश्चय ही ऐसे छेड़खानी के कथित आरोप को नैतिक दृष्टि से अनुचित ही कहा जाएगा, लेकिन उसका बदल हत्या कदापि नहीं हो सकती। यह दुखद है कि एक मृतक किशोर अरमान पांच बहनों का अकेला भाऊ था। घटना से उपजी त्रासदी से अरमान के परिवार पर हुए व्यवहार को सहज महसूस किया जा सकता है। उनके लिये जीवनभर न भुलाया जा सकने वाला दुख एवं संत्रास पैदा हुआ है। बड़ा सवाल है कि जिन वजहों से बच्चों के भीतर आक्रामकता एवं हिंसा पैदा हो रही है, उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? पाद्यक्रमों का स्वरूप, पढ़ाई-लिखाई के तीर-तीरे, बच्चों के साथ घर से लेकर स्कूलों में हो रहा व्यवहार, उनकी रोजमरा की गतिविधियों का दायरा, संगति सोशल मीडिया या टीवी से लेकर सिनेमा तक उसकी सोच-समझ को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से तैयार होने वाली उनकी मनःस्थितियों के बारे में सरकार, समाजकर्मी एवं अभिभावक द्वारा समाधान खोज रहे हैं। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा? बहरहाल, इस हृदयविदारक एवं त्रासद घटना ने नयी बन रही समाज एवं परिवार व्यवस्था पर अनेक सवाल खड़े किये हैं। निश्चित ही किसी परिवार की उम्मीदों का यूं कल्प होना मर्मातिक एवं खीफनाक ही है। लेकिन सवाल ये है कि चौदह-पंद्रह साल के किशोरों पर यूं किन्हीं लड़कियों को छेड़ने वें आरोप यद्यों लग रहे हैं? पढ़ने-लिखने की उम्र में ये सोच कहाँ से आ रही है? वयों हमारे अभिभावक बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं ताकि वे किसी की बेटी व बहन को यूं परेशान

न करे? यदों लड़कियों से छेड़छाड़ की अश्लीली एवं कामूक घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा का वह पक्ष उपेक्षित चला है, जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है? क्या शिक्षक छात्रों को सदाचारी व नैतिक मूल्यों की जीवन जीने की प्रेरणा देने में विफल हो रहे हैं? हत्या की घटना हत्यारों की मानसिकता पर इस सवाल उठाती है कि उन्होंने क्यों सोच लिया है कि छेड़खानी का बदला हिंसा एवं कूरुता से गठन काटना हो सकता है? धनीरी की घटना के पास माले की पुलिस अपने तरीके से जांच करेंगी लेकिन किशोर अवस्था में ऐसी घटना को अंजाम देने के पीछे बच्चे की मानसिकता का पता लगाया भी ज्यादा जरूरी है। दरअसल, दशाओं तक बॉलीवुड की हिंदी फ़िल्मों ने समाज एवं विशेषता किशोर पीढ़ी में जिस अपसंरक्षिति का प्रसार किया, आज हमारा समाज उसकी त्रासदी झोंक रहा है। इसमें दो राय नहीं कि किशोरवय में रक्तभट्टने का खतरा ज्यादा रहता है। अब तक हिन्दी सिनेमा से समाज के किशोरवय और युवाओं में गलत संदेश गया कि निजी जीवन के छेड़खानी ही प्रेम कहानी में तब्दील हो सकती है। हमारे टीवी धारावाहिकों की संवेदनहीनता गुमराह किया है। बॉवस आफिस की सफलता और टीआरपी के खेल ने मनोरंजक कार्यक्रमों के ऐसी नकारात्मकता एवं हिंसक प्रवृत्ति भर दी है कि किशोरों में हिंसक एवं अराजक सोच पैदा हुए हैं। इंटरनेट के विस्तार और सोशल मीडिया के प्रसार से स्वच्छ यौन व्यवहार का ऐसा अराजक प्राप्ति अनियन्त्रित रूप सामने आया कि जिसने किशोरों का युवकों को पथभ्रष्ट एवं दिग्भ्रमित करना शुरू कर दिया। आज संकट ये है कि हर किशोर व्याथ में आया मोबाइल उसे समय से पहले व्यवहार बना रहा है। जिस पर न परिवार का नियंत्रण और न ही शिक्षकों का। 'मन जो चाहे वही कर सकता है' की मानसिकता वह पनपती है जहां इंसानी रिश्ते

के मूल्य समाप्त हो चुके होते हैं, जहाँ व्यक्तिवादी व्यवस्था में बच्चे बढ़ाते होते होते स्वरूप हो जाते हैं। अर्थप्रधान दुनिया माता-पिता के पास बच्चे के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं बच पा रहा।

आज कि शोरों एवं युवाओं को प्रभावित करने वाले सोशल मीडिया एवं ऐलेट्रॉनिक व नये-नये एवं पश्चिमी अपसंस्कृति संचालित हैं। इन पर विकृतियों वाले कार्यक्रमों की बाढ़ है जिनमें सामाजिक रिश्तों में सहकारीकरण बनाने का खेल एवं सामाजिक उदासीनता बच्चों के पास सही जीवन सलीका नहीं होता। वर्तमान ऐसे बच्चों में मान-मर्यादा, आत्मीयता, शातिष्ठीपूर्ण रूप खास रुपाल नहीं रहता। एवं यौनाचार ही जीवन का एक है। भारतीय बच्चों में इन उनमें गहरी हताशा, तंत्रज्ञान एवं प्रतिशोध का भाव भर रखने वाला बन रहे हैं, वे आगे और अपने पास उपलब्ध हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रिया के ललाच और से किशोरों पर विचला है कि दुनिया भर में किशोर मानसिक तनाव एवं परिवारिक अथवा सामाजिक



अथवा अन्य कारणों से जूँड़ा रहे हैं। एकाकीपन बढ़ने से वे ज्यादा आक्रामक और विध्वंसक सोच की तरफ बढ़ने लगे हैं। मोबाइल व फ़ाक्टरी कथित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बह रहे नीले जहर से किशोर अराजक यीन व्यवहार एवं हिस्क प्रवृत्तियों की तरफ उन्मुख हुए हैं। किशोरों को समझाने वाला कोई नहीं है कि यह रास्ता आत्मघात का है। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व ब्रिटेन जैसे देश किशोरों को मोबाइल से दूर रखने हेतु कानून बना रहे हैं। हमारे देश में भी शीर्ष अदालत ने समय-समय पर ऐसी घटनाओं पर तल्ख टिप्पणियां की हैं। वया इन दर्दनाक घटनाओं से हमारे अभिभावकों, समाज-निर्माताओं एवं हमारे सत्ताधीशों की आंख खुलेगी? बच्चों से जुड़ी हिंसा की इन वीभत्स एवं त्रासद घटनाओं से जिन्दगी सहम गयी है। हमें मानवीय मूल्यों के लिहाज से भी विकास एवं नयी समाज-व्यवस्था की परख करनी होगी। बच्चों के भीतर हिंसा मनोरंजन की जगह ले रही है। इसी का नतीजा है कि छोटे-छोटे स्कूली बच्चे भी अपने किसी सहपाठी की हत्या तक कर रहे हैं। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बृन्दावन समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा?

संपादकीय

ईडी की विश्वसनीयता

यह कोई नई बात नहीं है कि देश की जांच एजेंसियों पर सरकार की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से पक्षपात के आरोप लगे हों। सरकारी जांच एजेंसियों को वे विपक्ष के नेताओं को डराने-धमकाने का हथियार बताते रहे हैं। अब इन्हीं चिंताओं और सवालों पर देश की शीर्ष अदालत ने भी मोहर लगाई है। विपक्षी नेता खासकर धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाइयों पर रोक लगाने की गुहार लगाते रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय सरकार के हितों की पूर्ति के लिये दुराग्रह से कार्रवाई करता है। हालांकि, अदालत का मानना रहा है कि भ्रष्टाचार, देशविरोधी गतिविधियों तथा आतंकवादी संगठनों को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अतार्किक नहीं है। सवाल इस बात को लेकर भी उठते रहे हैं जितने आरोप पत्र ईडी द्वारा दायर किए जाते हैं, उसकी तुलना में दोषसिद्धि की सख्ती में बेहद ज्यादा अंतर बर्द्धों है। जो इस बात की ओर इशारा करता है कि मामले दुराग्रह से प्रेरित होते हैं। अदालत भी मानती है कि ठोस प्रमाण के बिना किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक हालिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कारणजारियों पर कोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाते हुए सीमाएं लांघकर संघीय ढांचे के अतिक्रमण करने की बात कही है। कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु में शराब की दुकानों के लाइसेंस देने में बरती गई कथित धांधली में राज्य विपणन निगम के विरुद्ध धनशोधन मामले में ईडी की जांच पर की है। दरअसल, निगम द्वारा शीर्ष अदालत में मामला ले जाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जांच रोकी बल्कि ईडी की कारणजारियों पर सख्त टिप्पणियां भी की हैं। निस्संदेह, ईडी को इस सुप्रीम नसीहत पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि प्रवर्तन निदेशालय संघीय अवधारणा का उल्घन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि पीएमएलए की धाराओं के दुरुपयोग को लेकर शीर्ष अदालत पहले भी ईडी के खिलाफ सख्त टिप्पणी कर चुकी है। निस्संदेह, अदालत की इस सख्त टिप्पणी से उन तमाम विपक्षी दलों को सबल मिलेगा जो आए दिन ईडी व अन्य जांच एजेंसियों का सत्तापक्ष द्वारा दुरुपयोग करने का आरोप लगाते थे। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की दलील थी कि जिन शराब की दुकानों के लाइसेंस देने में अनियमिताओं के मामले में ईडी ने हस्तक्षेप किया है, उसमें वर्ष 2014 से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस मामले में चालीस से अधिक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। वहीं निगम कई मामलों में शिकायतकर्ता है। ऐसे में इस मामले में ईडी के कूदने पर सवाल उठे हैं। यही वजह है कि कोर्ट ने ईडी की इस जांच पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार भी ईडी की कार्रवाई को संवैधानिक अधिकारों व संघीय ढांचे का उल्घन बताती रही है। विश्वास किया जाना चाहिए कि कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद ईडी केंद्र की इच्छाओं के अनुरूप आंख बंद कर कार्रवाई करने की बाजार भपनी कार्रवाई में अपेक्षित परिवर्तन करेगी।

हमेशा समय के साथ चले, समय से कभी विलम्ब ना चले ऐ सवाल का जबाब रामायण में किसिकंधा कांड में पढ़ने को मिलता है जब माता सीता की खोज में सुग्रीव को चेताया था लोगों से सुनने को मिलता है कि भगवान् श्री राम ने वालि को धोखे से मारा ऐ गलत है प्रभु ने वालि को मोक्ष दिया धोखा से नहीं मारा था भगवान् श्री राम के पिता राजा दशरथ , बड़ी मुश्किल कैरई के वनवास को पूर्ण करने के लिए भगवान् राम को 14वर्ष के वनवास के लिए आदेश दे पाए होंगे। राजा, उनकी आँखें आँसुओं से भरी हुई थीं, उनका गल भावनाओं से भर गया था, वे केवल ये शब्द बोल पाएँ- राम और कुछ नहीं वास्तव में, राम ने बिना किसी सवाल के आदेश स्वीकार कर लिया। मैं पिता की आज्ञा का पालन करने में प्रसंग हूँ, उन्होंने कैरई से कहा- वयों, अगर आप आदेश दें तो भी मैं जाऊँगा। इस प्रकार, बिना किसी विरोध के, राम दयालुता और सद्व्यवना के एक बड़े इशारे में अपने 14 साल के वनवास की यात्रा पर निकल पड़ते हैं वह कैरई से वास्तव में अनुरोध करते हैं कि वह राई का पहाड़ न बनाए। उन्होंने उसे सात्वना भी दी और अनुरोध किया कि उसे इतनी छोटी सी बात पर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। राम को 14 साल जंगल में बिताना बहुत छोटी सी बात लगती थी। राम के सबसे वफादार छोटे भाई लक्ष्मण ने अब राम के साथ मिलकर राम के साथ किए गए अनुचित व्यवहार का शाही जयाब देने का फैसला किया। राम ने लक्ष्मण को समझाने की पूरी कोशिश की कि उन्हें परिवार की देखभाल करने के लिए वापस लौटना चाहिए और राज्य पर शासन करने में भरत की मदद भी करनी चाहिए। हालाँकि, लक्ष्मण ने उनकी बात नहीं मानी। हालाँकि लक्ष्मण राम के भाग्य या नियति के दर्शन से सहमत नहीं थे, लेकिन वे अपने बड़े भाई के बिना भी नहीं रह सकते थे। इस तरह यह बात सामने आई कि राम के पास अपने छोटे भाई को वनवास में अपने साथ ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राम के लिए मामले को और भी बदतर बनाने के लिए, उनकी युवा पत्नी सीता ने भी राम के साथ जाने का फैसला किया। सीता को समझाने के राम के

समय से कभी विलम्ब ना चले

(लेखक- संजय गोस्वामी)

भागने के दौरान अपना हार, कंगन और अगूठी धरती पर गिरा दी थी। पहाड़ी पर चढ़ने-उत्तरने, नदियों और मैदानों को पार करने के बाद, उन्हें सीता के छोटे-छोटे शरीर के आभूषण मिले। बड़े उत्साह के साथ, राम अब अपने भाई से कहते हैं- हे लक्षण, यहाँ, वह चिल्लाया, देखो मेरी सीता के सोने के झुम्के गिर गए हैं। यहाँ उसकी फटी हुई और फटी हुई मालाएँ हैं, यहाँ हर चमकता हुआ आभूषण पड़ा है। हे देखो, हर तरफ सोने के आभूषण व साथ में खून से जमीन भी रंगी हुई है। वे जो खून की बूँदें देखते हैं, वह जटायु नामक एक खून बहते हुए पक्षी की है। इस महान पक्षी ने सीता के अपहरणकर्ता रावण के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वर्यथ तो नहीं गया दयोंकि जटायु ने मरते मरते भगवान राम को सीता माता को रावण द्वारा हर कर ले जाने की खबर बता कर प्रभु की गोद में प्राण त्याग दिए। अपने मरने के क्षणों में, उसने राम को यह बताने की कोशिश की, संभवतः अपनी साकेतिक भाषा का उपयोग करके, कि उसने संकट में किसी युवती को जोर से और बार-बार चिल्लाते हुए सुना, हे राम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अपहरणकर्ता उड़ने वाली यान जैसी किसी चीज़ का इस्तेमाल किया था और दक्षिण की ओर जा रहा था। तब पक्षी ने अपनी अंतिम सौंस ली। उस सुराग के साथ, दोनों भाइयों ने सीता की खोज शुरू की, पहाड़ियों पर चढ़ते-उत्तरते और नदियों पार करते हुए, और भी बहुत कुछ! किस्मत से, राम अब 'किञ्चिधा' (अब भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित) नामक एक छोटे से राज्य में पहुँचते हैं। उस छोटे से राज्य पर तब वालि नाम का एक राजा राज करता था। कुछ लोग 'व' को 'व' में बदल देते हैं और उसे वाली कहते हैं। मैं 'व' के बजाय संस्कृत शब्द 'वालि' का उपयोग करना पसंद करता हूँ, ताकि कोई बाली का इडोनेशिया के उस नाम वाले शहर से भ्रमित न हो। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई वालि से लड़ता था, तो वालि को अपने दुश्मन की आधी ताकत हड्डपें की शक्ति प्राप्त हो जाती थी। यह शक्ति वास्तव में उसके नाम 'वालि' के अनुरूप है, जिसका अर्थ है ताकत। राम की मूलाकात वालि के छोटे भाई 'सुश्रीव' से होती है। सुश्रीव लगभग वैसी ही स्थिति में था जैसी उस समय राम थे।

(चिंतन- मनन)



धर्म का आदर

स्वामी ब्रद्धानंद महर्षि दयानंद के योग्य शिष्य थे। उन्होंने शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए देश के कई हिस्सों में गुरुकुल कांगड़ी और अन्य संस्थाओं की स्थापना की थी। एक बार रुड़की चर्च के पादरी फादर विलियम ने स्वामी जी से पत्र लिखकर कहा— स्वामी जी, मुझे लगता है कि अगर मैं हिंदी सीख लूं तो शायद भारत में मैं अपने धर्म का प्रचार बेहतर ढंग से कर पाऊंगा। क्या इसके लिए आप मुझे अपने गुरुकुल में प्रवेश दे सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि अपने अध्ययन के दौरान मैं ईसाई धर्म

की वर्चा नहीं करूँगा और उसके प्रचार की को कोशिश नहीं करूँगा। स्वामी जी ने पत्र के जवाब में लिखा- फादर गुरुकुल कांगड़ी में आपका खुले दिल से स्वागत है। आप यहां अतिथि बनकर हमारी सेवाएं तो सकते हैं। मगर आपको एक वधन देना होगा। जब तक आप यहां रहेंगे तब तक आप अपने धर्म का खुलकर प्रचार-प्रसार करेंगे ताकि हमारे छात्र भी इसा मसीह के उपदेशों को समझ सकें और उनका ग्रहण कर सकें। मैं चाहता हूँ कि हमारे छात्र धर्म

का आदर करना सीखें। धर्म प्रेम सिखाता है बैर
नहीं। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने अलावा
दूसरे धर्मों को भी जाने। अधिक से अधिक धर्मों के
विषय में जानकर हम एक अच्छे इंसान बन सकते
हैं।

स्वामी जा का यह जवाब पढ़कर फिर आभूत हो गए। वे जब तक गुरुकुल में रहे, छात्रों को ईसाई धर्म के बारे में बताते रहे। यहां रहकर भारतीयों को लेकर उनकी कई धारणाएं बदल गई।

विचार मंथन

प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही तय हो, लापरवाही पर कड़ी सजा

(लेखक- सनत जैन)

का पालन नहीं करने पर यह स्थिति के बल
अवमानना का मसला नहीं माना जाना चाहिए।
बल्कि शासन एवं प्रशासन तंत्र की मानसिकता
न्याय तंत्र को लेकर कैसी है। यह इस रिपोर्ट से
उजागर होती है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में
जिस तरह की माद लीचिंग, बुलडोजर न्याय,
शासन एवं प्रशासन के दबाव में पुलिस द्वारा
काल्पनिक अपराध कायम कर नागरिकों को
प्रमाणित किया जा रहा है। यह किसी से डिप्पा
नहीं है। समय-समय पर हाईकोर्ट एवं
सुप्रीमकोर्ट ने जौँच एजेंसियों, पुलिस और सक्षम
प्रशासनिक अधिकारियों के लिये निर्देश जारी
किये। किन्तु उनका पालन करने के स्थान पर
सततपक्ष के राजनेताओं के दबाव में जिस तरह से
असरैधानिक एवं कानूनों की अनदेखी हो रही है।
उससे न्यायपालिका की साख में सबसे ज्यादा
पिरागढ़ आई है। यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च

न्यायालय के आदेशों को लागू करने में सरकार या प्रशासनिक अधिकारी आनाकानी करें। यह न केवल लोकत्र के लिए संकट की स्थिति है, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक एवं भौतिक अधिकारों का भी खुला हनन है। विभागीय प्रमोशन, सेवा विस्तार या स्थानांतरण जैसे मुद्दों पर न्यायालयों के निर्देशों और आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। यह सिलसिला वर्षों तक खिचता है। प्रशासकीय अधिकारियों और शासन द्वारा लगातार अपील पर अपील की जाती हैं अतिम निर्णय आ जाने के बाद भी उसका पालन नहीं किया जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति नागरिक अधिकारों के मामलों में देखने को मिलती है। जहां प्रशासन नियम और कानून के विपरीत कार्यावाही करते हैं। न्यायालय से अंतिम फैसला भी हो जाता है। उसे सरकार के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लाग नहीं

किया जाता है। जब तक सरकार और प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी, न्यायिक आदेशों को लेकर जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। तब तक प्रशासन और न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। लोकतंत्र में हर किसी की जवाबदेही तय है। जब तक इस जवाब देही का सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा। सिर्फ चेतावनी या स्थानांतरण प्रशासकीय व्यवस्था को सुधारने के लिए काफी नहीं है। न्यायपालिका को गैर जिम्मेदार और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अनश्वासनात्मक कार्रवाई, आर्थिक दंड और कठोर सजा देने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अवमानना के प्रकरणों में प्रशासकीय अधिकारियों को कठोर दंड देकर, नसीहत देने की जरूरत है। ताकि आगे कोई भी

अधिकारी अदालत के आदेशों की अवमानना करने की हिम्मत न कर सके। सरकारों को चाहिए, वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को समरबद्ध न्यायिक आदेशों के पालन सुनिश्चित करने की जवाब देही तय हो। ऐसी स्थिति में न्यायालिका के आदेश पर शासन भी ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही कर उन्हें सेवा से हटाने का निर्णय भी कर सकती है। यदि ऐसा होगा तभी कानून का राज कायम हो सकेगा। न्याय पालिका की गिरिमा तथा लोकतात्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।

प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही की भावना को संस्थापित रूप से मजबूत करने की महत्व आवश्यक ता है। नागरिकों को भी अपने संवैधानिक एवं लोकतात्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। नागरिक जब जागरूक होंगे, तब प्रशासन के अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। अदालत में आपके पक्ष में फैसला हुआ है, उस आदेश के पूर्ण पालन होने तक तक नागरिकों को सज्जा रहने की जरूरत है। हर नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति संघेत रहेगा तभी नागरिकों के मौलिक और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे। नागरिकों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना होगी। कहा जाता है भरोसे की भैंस हमेशा पड़ा को जन्म देती है। स्वयं की लड़ाई कोई दूसरा लड़ने के लिए नहीं आएगा। अदालतों की भी, यदि उनके आदेश का पालन नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए संविधान ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को असीमित अधिकार दिए हैं। जिससे वह संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकें।

